मंगलवार, 3 फरवरी, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

अल्कराज बने टेनिस के नए बादशाह

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

आहान शेट्टी के हाथ लगी दूसरी फिल्म

Page-05

73 दिनों तक चला डोकलाम गतिरोध,

फिर क्यों गरमाई संसद?

• विपक्ष ने मांगा श्वेत पत्र, सत्ता पक्ष ने किया खंडन

- **राहुल गांधी ने उठाए सीमा सुरक्षा और कूटनीति पर सवाल**
- **• सरकार का पलटवार: "राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं"**

राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार पूर्व आर्मी चीफ की किताब पब्लिश नहीं करने दे रही है, क्योंकि अगर किताब पब्लिश होती है तो लोगों को मोदी सरकार की सच्चाई का पता चल जाएगा, कि जब चीन हमारे सामने खड़ा था तब 56 इंच की छाती का क्या हुआ? राहुल गांधी के सवाल पर संसद में जमकर हंगामा हुआ. लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने 8 साल पुराने उस वाकये को संसद में उठाकर सत्ता से सवाल पूछा, जब भारत और चीन की सेनाएं आमने-सामने आ गई थी. 73 दिनों तक चले इस टकराव ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था. दरअसल डोकलाम विवाद भारत के पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा हुआ है. इस जगह पर भारत, भूटान और तिब्बत (चीन) की सीमा एक साथ लगती हैं. भूटान जहां इसे अपना क्षेत्र मानता है तो वहीं चीन इसे अपने डोंगलांग प्रांत का हिस्सा बताता है. भारत के संबंध में यह जगह बेहद महत्वपूर्ण है. अगर इस जगह पर चीन का कब्जा होता है तो चीन पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली चिकन नेक के बेहद पास पहुंच सकता है. किसी युद्ध या तनाव की स्थिति में चीन इसे कॉरिडोर को काटकर पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग कर सकता है. इसलिए भारत और भूटान मिलकर चीन से लड़ते हैं. भूटान के साथ भारत का समझौता हुआ है जिसके तहत भारत भूटान की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. भारत, भूटान पर किसी विदेशी हमले की स्थिति में शांति का इंतजार नहीं कर सकता. इसलिए डोकलाम मामले पर भारत ने चीन को कड़ी टक्कर दी.

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में

सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप

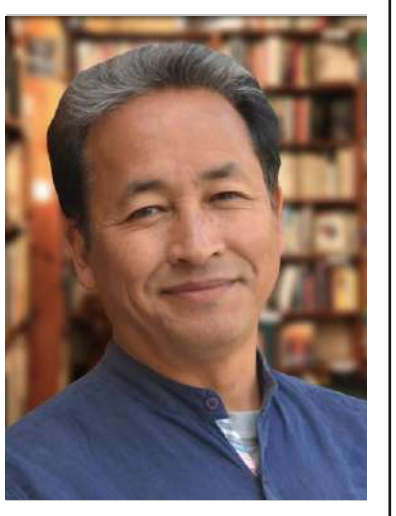

सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के संबंध में दायर याचिका के संबंध में सुनवाई के दौरान केंद्र ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया. केंद्र सरकार ने कहा कि वो लद्दाख को बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते थे. इस जहर को हम फैलने नहीं दे सकते हैं. सोनम वांगचुक को लद्दाख हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया है. इस समय वो जोधपुर जेल में बंद हैं.SC में इस याचिका की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना वी वराले की बेंच सुनवाई कर रही थी. वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र की तरफ से पक्ष रख रहे थे.

तुषार मेहता ने कहा कि वांगचुक के भाषणों में यह दिखता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं. जिले के डीएम ने उनकी गिरफ्तारी का फैसला लिया है. मेहता आगे कहते हैं कि इन्होंने अपने भाषणों में नेपाल और बांग्लादेश जैसे उदाहरण देते हैं, जो युवाओं को भड़काना और देश की एकता को तोड़ने के बराबर है. सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाने के लिए ये आधार पर्याप्त हैं. 10 सितंबर 2025 को लेह में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6वीं अनुसूचि के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए. इस दौरान सोनम वांगचुक भूख हड़ताल औऱ अनशन पर बैठे थे. 23 सितंबर को अनशन पर बैठे दो लोगों की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद लेह में बंद की अपील की गई. 24 सितंबर को बंद के दौरान हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए. प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों की गाड़ियों को फूंक दिया और बीजेपी कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया. इसपर काबू पाने के लिए सुरक्षाबलों ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया. इस प्रदर्शन में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए. सुरक्षा को देखते हुए लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया. जांच के दौरान पुलिस ने सोनम वांगचुक को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार पाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

नितिन नबीन निर्विरोध बने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष

बीजेपी में 'नबीन' युग

नई दिल्ली, आजतक

बीजेपी में 'नबीन' अध्याय शुरू हो रहा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया में नितिन नबीन ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया.

इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और गडकरी जैसे प्रमुख नेता मौजूद रहे. सूत्रों के मुताबिक, नितिन नबीन निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे और वह मंगलवार को अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे. 36 राज्यों में से 30 राज्यों के

प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई है, जो न्यूनतम 50% राज्यों की शर्त पूरी करने के लिए ज़रूरी संख्या से कहीं ज़्यादा है.

हिन्दी जगत महामंच

www.tvbharatvarsh.in

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर

प्रदेश का नं. 1 प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2- 3)	फुल पेज (कवर 4- अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

ट्रंप ने भारत के साथ बड़े व्यापार समझौते की घोषणा की-

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद भारत के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौता होने की घोषणा की है। इसके तहत अमेरिका ने भारत से आयात पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने का फैसला किया है।ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंधों और सम्मान को दर्शाता है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका आगे बढ़कर भारत के खिलाफ अपने शुल्क और गैर-शुल्क अवरोधों को हटाने की दिशा में भी काम करेगा।प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह "Made in India" उत्पादों पर शुल्क में कटौती को लेकर खुश और उत्साहित हैं। उन्होंने इस साझेदारी को दो बड़ी लोकतंत्रों के बीच सहयोग का उदाहरण बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर खुलेंगे।समझौते के तहत भारत ने यह भी प्रतिबद्ध किया है कि वह अमेरिकी माल पर अपने शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को धीरे-धीरे शून्य तक कम करेगा, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने रूसी तेल खरीद को रोकने और अमेरिका तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से ऊर्जा खरीद को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर भी सहमति जताई है।विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता भारत-अमेरिका आर्थिक रिश्तों को नई गति देगा, दोनों देशों के व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा और वैश्विक व्यापार संरचना में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।

"अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को ध्यान में रखकर 50 शहरों को किया जाएगा डिजाइन"

भारत को ऑल-सीजन डेस्टिनेशन, ग्लोबल टूरिस्ट-हब बनाने की तैयारी; टियर 2-3 सिटीज का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्र सरकार का साल 2026-27 के लिए बजट पेश किया। बजट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं हुई। वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक देश के 50 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास लेवल की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट के लिए तैयार किया जाएगा। इसका मकसद भारत को ऑल-सीजन डेस्टिनेशन और ग्लोबल टूरिस्ट-हब बनाना है। इस प्लान की मदद से एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, जिससे टियर 2-3 शहरों और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इससे देश का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा, साथ ही सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का अर्थ सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण कैसा हो, ये भी विकसित भारत का महत्वपूर्ण पहलू है। एक नागरिक के रूप में हमें अपने कर्तव्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 2,438.40 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक 10 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आएं। 2034 तक भारत की जीडीपी में पर्यटन का योगदान43.25 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। 6.3 करोड़ लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगा। पर्यटन मंत्रालय की इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल करीब 1 करोड़ विदेशी पर्यटक आते हैं। इनमें से 6–7% बौद्ध पर्यटक होते हैं। पिछले साल 7.10 लाख बौद्ध पर्यटक भारत आए। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए इस बार 6,812 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यह राशि पिछले बजट से 20% ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। मंदिरों के शहर के तौर पर पहचाने जाने वाले शहरों में बुनियादी सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की जरूरतों के अनुसार विकसित की जाएंगी। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मथुरा, जम्मू-कश्मीर का जम्मू, उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहरों पर फोकस रहेगा।

"ईरान ने EU राजदूतों को तलब किया, IRGC को आतंकी घोषित करने पर गुस्सा"

ईरान और यूरोपीय संघ के बीच कूटनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान ने अपनी अर्धसैनिक सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित करने के यूरोपीय संघ (EU) के फैसले के विरोध में सभी EU राजदूतों को तलब किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान को हाल के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर कथित हिंसक कार्रवाई और सामूहिक फांसी के मामलों के कारण अमेरिका से संभावित सैन्य कार्रवाई का खतरा झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी सेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत और कई मिसाइल विध्वंसक जहाजों को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य बल प्रयोग का फैसला लेंगे या नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय देश पश्चिम एशिया में एक और नए युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। दरअसल, यूरोपीय संघ ने पिछले सप्ताह ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई में IRGC की भूमिका के कारण इसे आतंकवादी संगठन घोषित करने पर सहमति जताई थी। इन प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत हुई और हजारों को हिरासत में लिया गया। अमेरिका और कनाडा सहित कई अन्य देश पहले से ही IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। हालांकि यह कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक माना जा रहा है, लेकिन इससे ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया है, खासकर इसलिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में IRGC की बड़ी भूमिका है।

"ग्रैमी 2026 में इतिहास रचा गया: स्टीवन स्पीलबर्ग और केंड्रिक लैमर सम्मानित, दलाई लामा और के-पॉप को भी मिला पुरस्कार"

"रूस के आसमान में अनोखा नज़ारा, एक साथ दिखाई दिए चार चंद्रमा"

रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आकाश प्रेमियों को रात के आकाश में चार चंद्रमाओं के एक साथ चमकने का अद्भुत नजारा देखकर मंत्रमुग्ध कर दिया। यह एक दुर्लभ और आश्चर्यजनक खगोलीय घटना है जिसे पैरासेलेनी के नाम से जाना जाता है।जिनमें पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के दोनों ओर कई चमकदार गोले दिखाई दे रहे थे। इस अनोखे दृश्य ने ऐसा भ्रम पैदा किया मानो चंद्रमा कई गुना बढ़ गया हो, जिससे दर्शक इस खगोलीय नजारे को लेकर आश्चर्यचकित और उत्सुक हो गए। इस घटना को आम तौर पर मून डॉग या मॉक मून कहा जाता है। यह कोई खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि चंद्रमा के प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाला एक प्रकाशीय भ्रम है। पैरासेलेना तब बनते हैं जब चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पतले, ऊँचाई पर स्थित सिरस या सिरोस्ट्रैटस बादलों से होकर गुजरता है जिनमें चपटे, षट्कोणीय बर्फ के क्रिस्टल होते हैं। जैसे ही प्रकाश इन क्रिस्टलों से होकर मुड़ता है, चंद्रमा के दोनों ओर चमकीले धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे कभी-कभी आकाश में कई चंद्रमाओं का आभास होता है। नासा के अनुसार, पैरासेलेना आमतौर पर चंद्रमा से लगभग 22 डिग्री या उससे अधिक के कोण पर दिखाई देते हैं। ये चंद्रमा की तुलना में बहुत धुंधले

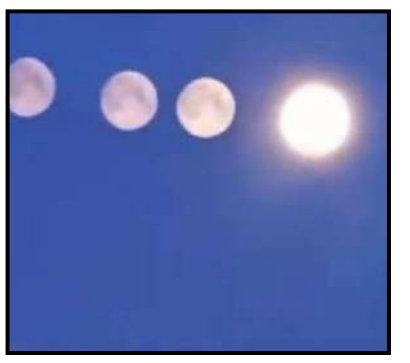

होते हैं और इन्हें तब देखना सबसे आसान होता है जब चंद्रमा क्षितिज पर नीचे होता है, क्योंकि कम चकाचौंध के कारण आसपास के प्रकाश पैटर्न अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये चमकीले धब्बे हमेशा क्षितिज से चंद्रमा के समान ऊंचाई पर रहते हैं। इनका आकार और तीव्रता बादलों में बर्फ के क्रिस्टलों की स्थिति और आकार पर निर्भर करती है। जब क्रिस्टल आकार में भिन्न होते हैं या गिरते समय डगमगाते हैं, तो पैरासेलेना लंबवत रूप से फैल सकते हैं, जिससे आकर्षक प्रकाश स्तंभ बनते हैं। स्काईब्रारी के अनुसार, बड़े बर्फ के क्रिस्टल ऊंचे और अधिक स्पष्ट प्रदर्शन उत्पन्न करते हैं, जिससे नाटकीय प्रभाव और बढ़ जाता है।

"SIR विवाद के बीच CM ममता बनर्जी करेंगी CEC ज्ञानेश कुमार से मुलाकात"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी. इस बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) होगा, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं. मुख्यमंत्री की इस यात्रा के दौरान कई कार्यक्रम तय हैं, जिनमें SIR के मुद्दे पर चर्चा प्रमुख रहेगी. इसके साथ ही ममता बनर्जी विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं ताकि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ एक साझा रणनीति और सहमति बनाई जा सके. तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अपनी दिल्ली यात्रा का समय बजट सत्र के दौरान रखा है, क्योंकि इस दौरान अधिकांश विपक्षी दलों के शीर्ष नेता राजधानी में मौजूद रहते हैं. हालांकि, कोलकाता लौटने की तारीख अभी तय नहीं हुई है लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी 5 फरवरी से पहले वापस आ जाएंगी क्योंकि उसी दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में 'वोट ऑन अकाउंट' पेश किया जाना है. बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र भी राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सदन में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. पहला प्रस्ताव राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों-सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका की निंदा से जुड़ा होगा. दूसरा प्रस्ताव राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया और उसके संचालन के तरीके के विरोध में लाया जाएगा. मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच होने वाली बातचीत को लेकर सियासी हलकों में पहले से ही कड़े रुख के संकेत मिल रहे हैं. हाल ही में ममता बनर्जी ने CEC को एक तीखे शब्दों वाला पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने विशेष रोल पर्यवेक्षकों (SROs) और माइक्रो-पर्यवेक्षकों की भूमिका और अधिकारों पर सवाल उठाए थे.

"50 साल पहले धरती के गर्म होने की भविष्यवाणी करने वाले रामनाथन को क्रैफोर्ड पुरस्कार"

भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 'रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज' ने भू-विज्ञान में 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार देने की घोषणा की है. ''भू-विज्ञान का नोबेल" कहे जाने वाले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत रामनाथन को 'सुपर-प्रदूषकों' और वायुमंडलीय 'ब्राउन क्लाउड्स' पर दशकों तक किए गए उनके शोध के लिए सम्मानित किया गया है, जिसने वैश्विक ताप वृद्धि (ग्लोबल वॉर्मिंग) की समझ को नई दिशा दी. 82 साल के रामनाथन ने 1975 में नासा में काम करते हुए एक ऐतिहासिक खोज की थी. उन्होंने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC), जो एरोसोल और रेफ्रिजरेशन में व्यापक रूप से इस्तेमाल होते थे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 10,000 गुना अधिक प्रभावी तरीके से गर्मी खींचते हैं. रामनाथन का जन्म मदुरै में हुआ और उनका पालन-पोषण चेन्नई में हुआ. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिकंदराबाद की एक

रेफ्रिजरेटर फैक्टरी में इंजीनियर के रूप में की थी, जहां उन्होंने पहली बार CFC पर काम किया. बाद में उन्होंने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और भारतीय विज्ञान संस्थान से उच्च शिक्षा प्राप्त की. क्रैफोर्ड पुरस्कार के तहत उन्हें लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि और एक स्वर्ण पदक दिया जाएगा. यह पुरस्कार मई 2026 में स्टॉकहोम में आयोजित 'क्रैफोर्ड डेज' के दौरान प्रदान किया जाएगा. रामनाथन का शोध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौतों की बुनियाद बना, जिसने वातावरण में लाखों टन हानिकारक उत्सर्जन को जाने से रोका है.

संपादक की कलम से

भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में समानता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक मजबूती की बुनियाद है। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और वर्ग के आधार पर सदियों से चले आ रहे भेदभाव ने भारतीय समाज को गहरे घाव दिए हैं। इन्हीं ऐतिहासिक अन्यायों को समाप्त करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान और उससे जुड़े विभिन्न कानूनों ने भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त और स्पष्ट ढांचा तैयार किया है।भारतीय संविधान का मूल दर्शन ही समानता पर आधारित है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 15 राज्य को जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से रोकता है। यह केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि उस सामाजिक संकल्प का प्रतीक है, जो भारत को एक समतामूलक राष्ट्र बनाना चाहता है।इतिहास साक्षी है कि भारतीय समाज में जाति आधारित भेदभाव सबसे गहरा और दीर्घकालिक रहा है। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने केवल समानता की घोषणा भर नहीं की, बल्कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी किए। आरक्षण नीति, शिक्षा और रोजगार में विशेष अवसर, तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे कानून इस बात को स्वीकार करते हैं कि समान अवसर तभी संभव हैं, जब असमान परिस्थितियों को पहले सुधारा जाए।महिलाओं के खिलाफ ऐतिहासिक भेदभाव को देखते हुए भी भारतीय कानूनों ने समय-समय पर ठोस हस्तक्षेप किया है। दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव कानून—ये सभी केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि समाज में लैंगिक न्याय की दिशा में उठाए गए आवश्यक कदम हैं।हालांकि, यह भी एक सच्चाई है कि कानून तभी प्रभावी होते हैं जब उनका क्रियान्वयन ईमानदारी से किया जाए। आज भी सामाजिक भेदभाव के कई रूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं। कभी परंपरा के नाम पर, कभी पहचान की राजनीति के सहारे, तो कभी आर्थिक और शैक्षणिक असमानताओं के रूप में भेदभाव नए रूप लेकर सामने आता है। ऐसे में केवल कानून का होना पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और संस्थागत जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है।एक स्वस्थ लोकतंत्र में भेदभाव विरोधी कानूनों का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार होना चाहिए। इन कानूनों का प्रयोग सामाजिक संतुलन स्थापित करने के लिए हो, न कि सामाजिक विभाजन को और गहरा करने के लिए। ऐतिहासिक अन्यायों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष, तर्कसंगत और भविष्य उन्मुख बनी रहे।संविधान ने भारत को केवल अधिकार नहीं दिए, बल्कि कर्तव्यों की भी याद दिलाई है। अंततः, भारतीय संविधान और कानून भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत ढाल जरूर हैं, लेकिन समाज की वास्तविक परीक्षा उसके व्यवहार में होती है। समानता केवल कानूनी किताबों में नहीं, बल्कि सामाजिक आचरण में उतरनी चाहिए। तभी भारत अपने संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, समावेशी और सशक्त राष्ट्र बन सकेगा।

"अतीत के भेदभाव के नाम पर सवर्णों के वर्तमान-भविष्य पर कानूनी शिकंजा, क्या यह न्यायसंगत है?"

भारत में भेदभाव रोकने के लिए संविधान और विभिन्न कानून प्रमुख भूमिका निभाते हैं, खासकर जाति, नस्ल या लिंग आधारित ऐतिहासिक भेदभाव के खिलाफ। ये प्रावधान समानता सुनिश्चित करते हैं और दंडनीय अपराध बनाते हैं।

अतीत के भेदभाव को आधार बनाकर सवर्ण समाज के वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को दंडित करने या आरक्षण जैसी नीतियों से बांधना न्यायसंगतता के सिद्धांतों के विरुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत योग्यता को नजरअंदाज कर सामूहिक दोषारोपण करता है। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि अतीत में हुए भेदभाव पर सवर्णों के वर्तमान-भविष्य को कानूनी शिकंजे में कसना दलित-ओबीसी नेतृत्व की न्यायसंगतता का तकाजा नहीं है! लिहाजा, उन्मुक्त हृदय से उनके मौजूदा प्रगतिशील नेताओं को गहराई पूर्वक विचार करना चाहिए और अपने पूर्वजों के प्रतिगामी नजरिए को बदलकर स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के राष्ट्रव्यापी लोकतांत्रिक भाव को मजबूत करना चाहिए। अन्यथा सामाजिक विघटन को परमाण्विक प्रक्रिया तेज होगी और इससे पैदा हुए जनविद्वेष की आग में देर-सबेर हरेक शांतिप्रिय लोगों के भी झुलसने का आसन्न खतरा बना रहेगा। ऐसा इसलिए कि यह नीतिगत, वैधानिक और रणनीतिक सवाल है जिसे कूटनीतिक स्वार्थवश विदेशों से हवा दी गई, इसे संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया, जिससे जातिविहीन हिंदुत्व के राष्ट्रवादी विचार को गहरा धक्का लगा है। जहां तक इस कुत्सित सोच की वैधानिक न्यायसंगतता के आधार का सवाल है तो भारतीय संविधान समानता (अनुच्छेद 14-16) और सामाजिक न्याय पर जोर देता है, लेकिन अतीत के अपराधों के लिए वर्तमान निर्दोषों को "सजा" देना प्रतिशोधात्मक लगता है, जो अबतलक बदस्तूर जारी है। इसलिए कहीं न कहीं यह सामाजिक एकता को कमजोर करता प्रतीत होता है। वहीं, जहां तक इस आशय की हुई क्षतिपूर्ति की अवधारणा की बात है तो यह अतीत-वर्तमान के अंतर्संबंध पर आधारित है, परंतु यह तब न्यायपूर्ण होती है जब यह पीड़ितों को शक्ति प्रदान करे, न कि नए भेदभाव को जन्म दे। खासकर भारतीय संदर्भ में जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (SC/ST/OBC) आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय सुधारने का ब्रितानी और भारत सरकार का विषैला सियासी प्रयास है, किंतु यूजीसी बिल (2026) जैसे नए प्रतिगामी नियमों व

कदमों के दुरुपयोग की आशंका पैदा करते हैं, जहां झूठे आरोप सामाजिक कड़वाहट बढ़ा सकते हैं। यह ठीक है कि रोहित वेमुला या पायल तडवी जैसे मामले दर्दनाक हैं, लेकिन नीतियां ऐसी हों जो योग्यता और समावेश को प्राथमिकता दें। ऐसा इसलिए कि एक तो छात्र राजनीति से पढ़ाई-लिखाई पर आंच आई, विश्वविद्यालय कैम्प्स की गरिमा गिरी है और अब उन्हें जातीय नजरिए से बांटना आग से खेलने जैसा मूर्खता भरा सियासी कदम है। इससे सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की तरह ही जातिवादी राष्ट्रवाद की भावना को बल मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि हमारा सत्ता प्रतिष्ठान वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित करे। मेरे विचार से शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक उत्थान से भेदभाव दूर करना अधिक न्यायसंगत है, क्योंकि संस्थागत भेदभाव को समाप्त करने से भविष्य स्वाभाविक रूप से समान बनेगा।

कहना न होगा कि अतीत को याद रखना जरूरी है, किंतु वर्तमान को उसके बोझ से मुक्त रखना ही सामाजिक प्रगति का आधार है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिन्नावादी सांप्रदायिक सोच से निरंतर झुलस रहे भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रितानी और अंबेडकरवादी/लोहियावादी जातिवादी सोच से विखंडित करने का जो मूर्खतापूर्ण सरकारी प्रयास जारी है, उससे जब सत्तर साल बाद भी मुट्ठीभर दलित-आदिवासी-ओबीसी की ही भलाई हो पाई है और उनमें भी नवसामंती भावना प्रबल हुई है, जिससे विखंडित जनादेश आने से अवसरवाद बढ़ा है। यह भारत के समावेशी विकास में भी अब बाधक बनता प्रतीत होता है। यह ठीक है कि भारत में जातिगत भेदभाव के लिए क्षतिपूर्ति मुख्यतः सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के रूप में लागू होती है, जो ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का प्रयास करती है। क्योंकि यह आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और विधायी सुरक्षा के माध्यम से कार्य करती है। इस हेतु संवैधानिक प्रावधान भी नियत हैं।भारतीय संविधान अनुच्छेद 15, 16, 46 और 335 के तहत SC/ST/OBC को शिक्षा, नौकरियों और विधायी सुरक्षा प्रदान करता है, जो भेदभाव रोकने और उत्थान सुनिश्चित करने के लिए हैं। वहीं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। जबकि SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अपराधों पर दंड और पीड़ितों को राहत देता है। आरक्षण सम्बन्धी प्रमुख नीतियां भी स्पष्ट हैं। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27% कोटा नियत है। इसी आधार पर उन्हें छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। उन्हें पोस्ट-मैट्रिक, प्री-मैट्रिक और अन्य योजनाएं वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। वहीं, कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वरोजगार ऋण, कौशल विकास और आवास योजनाएं (जैसे अंबेडकर आवास योजना) से भी उन्हें लाभान्वित किया जाता है। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब सवर्णों को भी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, लेकिन अन्य सहूलियत उन्हें मिलना अभी बाकी है।

"लोकसभा में राहुल गांधी का दावा: लद्दाख बॉर्डर तक पहुंचे चीनी टैंक"

लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए कहा- 4 चीनी टैंक लद्दाख सीमा में पहुंच गए थे। राहुल के ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री शाह ने उन्हें टोका। इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका। राहुल करीब 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल ने बोलना शुरू किया। लेकिन हंगामे के चलते महज 9 मिनट बाद ही कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 4 बजे भी कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामा हुआ और 11 मिनट बाद कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी संसद में जिस किताब के आधार पर डोकलाम में चीनी टैंक घुसने का दावा कर रहे हैं, वह पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने लिखी है। 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' नामक यह किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। इसका हार्डकवर अप्रैल 2024 से ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर उपलब्ध है। किताब में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की झड़पों के साथ-साथ अग्निवीर योजना को रिव्यू किया गया है। 2019 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे नरवणे ने इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी किताब पेंग्विन पब्लिशर ग्रुप को छपने के लिए दे दी है। अब यह प्रकाशन समूह और सरकार के बीच का मामला है। किताब रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी गई है। एक साल से ज्यादा हो चुका है लेकिन इसे पब्लिश करने की मंजूरी नहीं मिली है।

विजय ने DMK और AIADMK पर साधा निशाना:

TVK का गठन लोगों के आंसू पोंछने के लिए हुआ है

टीवीके चीफ और एक्टर विजय ने एक बार फिर सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और उसकी विरोधी एआईएडीएमके पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार की सुबह राज्य के राजनीतिक दिग्गजों पर जमकर हमला किया। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी को अपना राजनीतिक दुश्मन बताया है। हालांकि, उन्होंने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रति ज्यादा नरमी दिखाई। टीवीके चीफ और एक्टर विजय ने एक बार फिर सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और उसकी विरोधी एआईएडीएमके पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार की सुबह राज्य के राजनीतिक दिग्गजों पर जमकर हमला किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी को अपना राजनीतिक दुश्मन बताया है। हालांकि, उन्होंने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रति ज्यादा नरमी दिखाई। एक्टर ने उन आलोचकों को भी जवाब दिया

जिन्होंने उनके राजनीतिक अनुभव की कमी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद भी एमजीआर को छोटा समझा गया था।

विजय ने कहा, "यह उनका (यानी डीएमके का, जिसके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन और सरवनन ने विजय को वीकेंड पॉलिटिशियन कहा था और कहा था कि उन्हें जमीनी राजनीति की बारीकियों की जानकारी नहीं है) काम है। अब वे मेरे अनुभव पर सवाल उठा रहे हैं।"

एक्टर विजय ने अपनी पार्टी टीवीके के माध्यम से सत्ताधारी DMK और विपक्षी AIADMK पर निशाना साधा है। उन्होंने DMK को अपना राजनीतिक दुश्मन बताया और कहा कि TVK का गठन लोगों के आंसू पोंछने के लिए हुआ है। विजय ने आलोचकों को भी जवाब दिया, जो उनके राजनीतिक अनुभव पर सवाल उठा रहे थे, और DMK पर अन्याय व कानूनहीनता का आरोप लगाया।

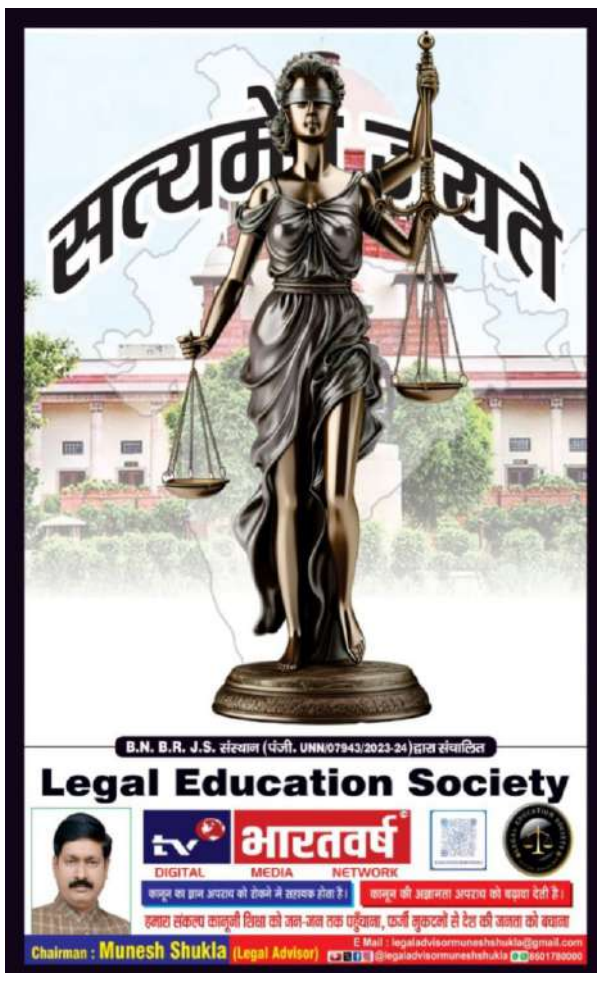

"10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड जारी, राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से"

राजस्थान बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। स्कूल आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर छात्रों को देंगे। बिना एडमिट कार्ड और फोटो आईडी के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है। बोर्ड के अनुसार, छात्र सीधे वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। सभी स्कूलों को अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और इसके बाद उन्हें छात्रों में वितरित करना होगा।कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक होंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक निर्धारित किया गया है। राज्यभर में इन परीक्षाओं के लिए कुल 6,193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 51 परीक्षा केंद्रों पर निगरानी (Surveillance) व्यवस्था की जाएगी, ताकि परीक्षाओं में अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहे।एडमिट कार्ड में छात्रों का नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, परीक्षा की तिथि और समय सहित परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल होंगे। बोर्ड ने छात्रों को विशेष रूप से सलाह दी है कि वे परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड में दर्ज सभी जानकारियों की अच्छी तरह से जांच करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें।बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड परीक्षा के दौरान अनिवार्य होगा। इसके बिना कोई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा।

जोकोविच का 25 ग्रैंड स्लैम का सपना टूटा

सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना चकनाचूर हुआ। हालांकि, जोकोविच के पास लगभग हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडरर और रफेल नडाल के बनाए रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक अधिक खिताब है। सेरेना के नाम महिलाओं के ओपन युग के रिकॉर्ड 23 एकल खिताब हैं। जोकोविच अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लेते तो मार्गरिट कोर्ट को पछाड़ देते है। जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट के नाम संयुक्त रूप से 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब का सर्वकालिक रिकॉर्ड है। उन्होंने सेमीफाइनल में यानिक सिनर को मात दी थी। जोकोविच लगातार चार मेजर में सेमीफाइनल से बाहर होने का सिलसिला खत्म करने के बाद अपने 11वें ऑस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल में पहुंचे थे। जोकोविच ने कहा, ''सबसे पहले एक शानदार टूर्नामेंट और शानदार दो हफ्तों के लिए बधाई।" उन्होंने कहा, "आप जो कर रहे हैं उसे बताने के लिए सबसे अच्छा शब्द ऐतिहासिक, दिग्गज है इसलिए बधाई। मैं आपके बाकी करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

सर्जरी के बाद तिलक वर्मा लौटे टीम इंडिया में, T20 World Cup से पहले वार्म-अप मैच में उतरेंगे"

"रिकी पोंटिंग ने T20 World Cup से पहले दिया अलर्ट, ऑस्ट्रेलिया भी टाइटल के दावेदार"

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि उनके पास अपना दूसरा खिताब जीतने का "किसी भी टीम के बराबर" मौका है और उन्होंने टीम में मौजूद कई ऑलराउंडरों की वजह से टीम की लचीलेपन पर जोर दिया। पोंटिंग, जो सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ ऑस्ट्रेलियाई कप्तानों में से एक हैं और जिन्होंने टीम को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2003 और 2007 तथा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2006 और 2009 में जीत दिलाई, आईसीसी रिव्यू के नवीनतम एपिसोड में बोल रहे थे। पोंटिंग ने यह भी बताया कि डेविड वार्नर (सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से) और मिशेल स्टार्क (टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से) के संन्यास के बाद टीम में थोड़ा बदलाव होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। चोटिल तेज गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड के बिना भी, ऑस्ट्रेलिया के पास जेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस जैसे प्रतिभाशाली और विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। भारत और श्रीलंका की पिचें स्पिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल होने के कारण, पोंटिंग का मानना है कि श्रीलंका में खेले जाने वाले ग्रुप चरण में ऑस्ट्रेलिया तीन स्पिन विकल्पों के साथ शुरुआत करेगा।

"T20 World Cup: भारत से मैच बॉयकॉट पर ICC और BCCI ने पाकिस्तान को कड़े संकेत दिए"

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज मैच के बहिष्कार के संबंध में खेल भावना पर आईसीसी के रुख से सहमत है और आईसीसी से परामर्श करने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करेगा। बीसीसीआई उपाध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि आईसीसी ने एक बड़ा बयान जारी किया है, उन्होंने खेल भावना की बात की है। हम आईसीसी से पूरी तरह सहमत हैं। आईसीसी से बात करने तक बीसीसीआई इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। राजीव शुक्ला की यह टिप्पणी तब आई है जब पाकिस्तान ने 15 फरवरी को होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पाकिस्तान सरकार ने एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। रविवार को एक पोस्ट में पाकिस्तान सरकार ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान की सरकार आईसीसी विश्व टी20 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी को मंजूरी देती है; हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में नहीं खेलेगी। पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ न खेलने के अपने फैसले का कोई कारण नहीं बताया। भारतीय टीम विश्व कप से पहले शानदार फॉर्म में है और उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से जीती है। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण के मैच का बहिष्कार करने के कुछ घंटों बाद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने कहा कि "चुनिंदा भागीदारी" "वैश्विक खेल आयोजन के मूल सिद्धांतों" के अनुरूप नहीं है और वह पीसीबी से सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने वाले पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने की उम्मीद करती है।

"ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर कार्लोस अल्काराज बने टेनिस के नए बादशाह"

कार्लोस अल्काराज़ ने आज इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और दिग्गज नोवाक जोकोविच को हराया, जो अपना 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, 22 वर्षीय अल्काराज़ ने संयम बनाए रखते हुए 22 साल और 272 दिन की उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए और 88 साल बाद डॉन बज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि यह अल्काराज़ की पहली ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत है, लेकिन इससे पहले वह छह ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके थे। मैच की बात करें तो, अल्काराज़ ने बेहद दबाव में मैच की शुरुआत की क्योंकि जोकोविच बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे थे और उन्होंने पहला सेट 6-2 के अंतर से जीत लिया। हालांकि, स्पेनिश खिलाड़ी को अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने दूसरे सेट में शानदार 6-2 की जीत के साथ स्कोर बराबर कर लिया। तीसरे सेट की शुरुआत होते-होते, ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में सबसे युवा और सबसे अनुभवी खिलाड़ी के बीच मुकाबला शुरू हो गया। कार्लोस अल्काराज़ अपनी बेहतरीन फिटनेस का प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि जोकोविच हर गेम के साथ थकते जा रहे थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 22 वर्षीय खिलाड़ी को लगभग हर पॉइंट के लिए कड़ी मेहनत करवाई और कई ब्रेक पॉइंट बचाकर खेल में बने रहे। लेकिन अंततः, अल्काराज़ ने तीसरा सेट भी अपने नाम कर लिया। चौथे सेट में, दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी सर्विस बचाने के मामले में बराबरी पर थे और 5-5 के स्कोर पर ऐसा लग रहा था कि सेट टाई-ब्रेकर में जाएगा। जोकोविच सराहनीय संघर्ष कर रहे थे, वहीं अल्काराज़ भी अपनी तीव्रता कम नहीं होने दे रहे थे। लेकिन चौथे सेट में आखिरी बार अपनी सर्विस बचाने की बारी आने पर, जोकोविच असफल रहे, या शायद उस शाम अल्काराज़ की श्रेष्ठता के आगे फीके पड़ गए। सर्बियाई खिलाड़ी ने कड़ा मुकाबला किया और स्पेन के चैंपियन खिलाड़ी ने अपने करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। कुल मिलाकर, यह सातवीं बार है जब अल्काराज़ ने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है और वह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं।

2026 में दुनिया खत्म होने संबंधी कई मीम्स और रील्स वायरल

प्रलय का डर या अफवाहों का शोर?

नए साल 2026 के साथ ही दुनिया के अंत की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं. सोशल मीडिया पर वायरल दावों की जड़ 1960 में वैज्ञानिक हेंज वॉन फोस्टर की भविष्यवाणी और 'डूम्सडे क्लॉक' से जुड़ी आशंकाएं हैं, हालांकि ये चेतावनियां प्रतीकात्मक हैं, न कि तय प्रलय की घोषणा.

चारों तरफ नए साल का जश्न मनाया जा रहा है. 2026 का आगमन हो चुका है. ऐसे में 2025 में पूरे साल ये चर्चा होती रही कि 2026 में तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी. इस पर सोशल मीडिया पर कई मीम्स और रील्स भी वायरल हुए. क्या सच में क्या 2026 में प्रलय आ जाएगी? क्या इसी साल कयामत का दिन आने वाला है.द प्रोविंस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, हेंज वॉन फोस्टर नाम के 1960 में एक भविष्यवाणी की थी कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी. अब सवाल उठता है कि 1960 में 2026 को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई थी. क्या उस भविष्यवाणी में दुनिया के अंत को लेकर कोई समय या तिथि की भी घोषणा की गई थी? टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भौतिक विज्ञानी हेंज वॉन फोस्टर , जिनका 2002 में निधन हो गया, उन्होंने 1960 में "साइंस" नामक पत्रिका में दावा किया था कि दुनिया 2020 के दशक में कभी भी समाप्त हो सकती है. हेंज वॉन फोस्टर ने दावा किया था कि 13 नवंबर, 2026 को दुनिया का अंत हो जाएगा. उन्होंने 1960 में "साइंस" नामक पत्रिका में दावे करते हुए इस विशेष दिन की भविष्यवाणी की थी.

दुल्हन की सहेलियों ने भी लिए 7 फेरे!

अक्सर ही सोशल मीडिया पर शादियों से जुड़ी इमोशनल या दुल्हा- दुल्हन के झगड़े की वीडियो तेजी से वायरल होती हैं. लेकिन हाल के समय में वायरल हो रही वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई खूब हंस रहा है. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरह दुल्हन की सहेलियां उसके लिए ओवर-केयरिंग हैं, जो माहौल को बदल देता है और हंसी में बदल देता है.

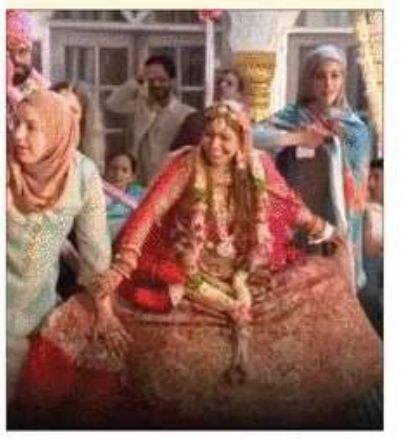

1.7 करोड़ कर्ज लिए, देने पड़ रहे 146 करोड़

सिंगापुर से सामने आई एक कर्ज की कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां एक व्यक्ति ने एक लाइसेंस प्राप्त मनीलेंडिंग कंपनी से दो लाख पचास हजार सिंगापुर डॉलर (करीब 1.7 करोड़ रुपए) उधार लिए थे, लेकिन ऊंची ब्याज दरों, लेट फीस और पेनल्टी के चलते उसकी देनदारी बढ़कर लगभग इक्कीस मिलियन सिंगापुर डॉलर (करीब 146 करोड़ रुपए) तक पहुंच गई. हालात ऐसे बने कि कर्ज के दबाव में उसे अपना घर तक बेचना पड़ा. द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कर्ज 2010 से 2011 के बीच लिया गया था. मनीलेंडिंग कंपनी ने इस पर चार प्रतिशत प्रति माह की ब्याज दर लगाई. इतना ही नहीं, समय पर भुगतान न होने की स्थिति में आठ प्रतिशत प्रति माह की अतिरिक्त लेट पेमेंट ब्याज भी वसूली जाती थी. इसके अलावा हर महीने ढाई हजार सिंगापुर डॉलर की लेट पेमेंट प्रोसेसिंग फीस भी जोड़ी जाती रही.

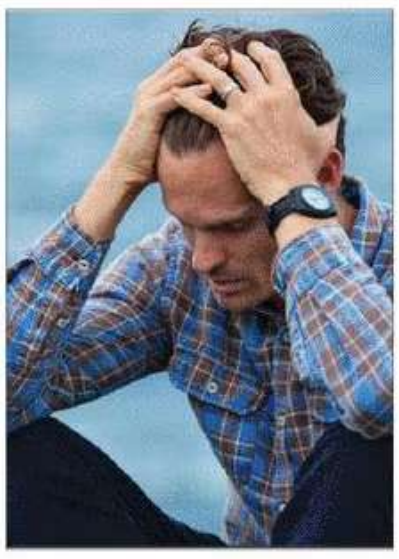

महिला ने शौकिया कराई थी जांच

DNA टेस्ट में सौतला पिता ही निकला असली

एक महिला अचानक डीएनए टेस्ट कराने के बाद अपने पिता के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई जानकर दंग रह गई. उसने बताया कि कैसे उसके पति ने अपने डीएनए के नतीजे आने के बाद उसे भी टेस्ट कराने के लिए प्रेरित किया.

इसके बाद महिला ने भी बिना किसी उद्देश्य के शौकिया डीएनए टेस्ट करवा लिया. फिर उसके मन में अपने डीएनए इतिहास के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई. मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला के जिंदगी में उसके पिता की भूमिका हमेशा से संदेहास्पद रही थी. पिता की भूमिका को लेकर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लेकर वह बड़ी हुई थी. उसने रेडिट पर कहा कि मुझे और मेरे दो बड़े भाई-बहनों को हमारे नाना-नानी ने बचपन में ही गोद ले लिया था. जब मेरी मां ने हमें जन्म दिया था तब वह बहुत कम उम्र की थीं. मेरी मां हमेशा हमारे जीवन में आती-जाती रही हैं, लेकिन वह स्थायी रूप से हमारे साथ कभी नहीं रहीं. क्योंकि वह नशे की लत से पीड़ित रही हैं और जेल भी गई हैं. बचपन में हम तीन भाई-बहन थे और मुझे छोटी उम्र से ही पता था कि मेरे दो बड़े भाई-बहनों के पिता मेरे पिता नहीं हैं.

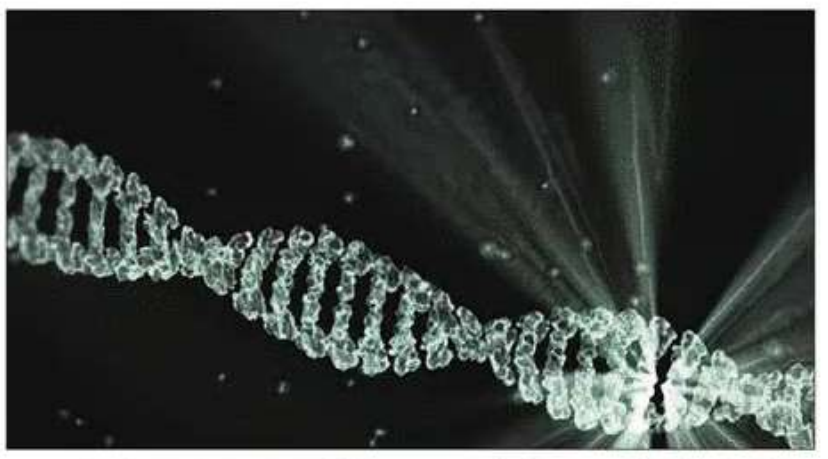

इसलिए वे मेरे साथ अलग तरह का व्यवहार करते थे और हमेशा मुझे यह जताते रहते थे कि मैं उनकी सौतेली बहन हूं.उसे बताया गया था कि उसके पिता एक "बड़े व्यक्ति" थे और वहीं मेरी परवरिश के लिए पैसे देते थे.

आहान शेट्टी के हाथ लगी दूसरी फिल्म

दिखेगा रोमांटिक अवतार-

फिल्म बॉर्डर 2 की सफलता ने जहां देशभक्ति फिल्मों के प्रति दर्शकों का उत्साह फिर से जगा दिया है, वहीं इस फिल्म से जुड़े कलाकारों के करियर को भी नई रफ्तार मिली है। इसी कड़ी में अभिनेता आहान शेट्टी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। दमदार एक्शन और इमोशनल किरदार से दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब आहान अपने करियर के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल अलग अंदाज़ में नजर आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक, आहान शेट्टी ने एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म साइन की है, जिसमें उनका किरदार संवेदनशील, गहराई से प्यार करने वाला और भावनात्मक रूप से जूझता हुआ युवा होगा। यह फिल्म एक आधुनिक प्रेम कहानी बताई जा रही है, जिसमें रिश्तों की जटिलता, करियर और निजी जीवन के टकराव, और सच्चे प्यार की परख जैसे पहलुओं को दिखाया जाएगा।निर्माताओं का कहना है कि वे आहान की स्क्रीन प्रेज़ेंस और मासूमियत को इस बार एक सॉफ्ट, इमोशनल लवर बॉय के रूप में पेश करना चाहते हैं। बॉर्डर 2 में उनके गंभीर और अनुशासित सैनिक अवतार के बाद यह बदलाव दर्शकों के लिए नया अनुभव होगा। इंडस्ट्री विश्लेषकों का मानना है कि यह फिल्म आहान की अभिनय क्षमता की नई परतें सामने ला सकती है। फिल्म की शूटिंग इसी साल के मध्य से शुरू होने की संभावना है। मेकर्स एक फ्रेश जोड़ी के साथ आहान को कास्ट करने पर विचार कर रहे हैं ताकि कहानी में नई केमिस्ट्री देखने को मिले। संगीत भी इस फिल्म की खास ताकत बताया जा रहा है, जिसमें कई मेलोडियस ट्रैक होंगे। फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि आहान शेट्टी अब सिर्फ एक्शन हीरो की छवि तक सीमित नहीं रहना चाहते। दर्शकों को जल्द ही उनका रोमांटिक, भावुक और दिल छू लेने वाला रूप बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकता है।इसके अलावा, फिल्म के निर्माताओं का लक्ष्य युवाओं से जुड़ने वाली एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी पेश करना है, जो संगीत और भावनाओं के दम पर दर्शकों के दिलों में जगह बना सके।अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा, तो यह फिल्म आहान शेट्टी के करियर की दिशा बदलने वाली साबित हो सकती है।फिल्म की कहानी को आज के दौर के रिश्तों से जोड़कर लिखा जा रहा है, ताकि युवा दर्शक खुद को किरदारों में महसूस कर सकें।ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रोजेक्ट आहान को रोमांटिक स्टार की नई पहचान दिला सकता है।

"CM योगी ने बताया जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत का समय, PM मोदी कर सकते हैं उद्घाटन"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। इसके शुरू होने के बाद यह उत्तर प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। इसके शुरू होने के बाद यह उत्तर प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि एयरपोर्ट तैयार है और एयरोड्रम लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री द्वारा इस महीने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर किया जाएगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसे गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (P P P) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। लगभग 1,300 हेक्टेयर में फैले इस प्रोजेक्ट के पहले चरण का संचालन शुरू में सितंबर 2024 में शुरू होने वाला था और यह कई डेडलाइन चूक चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही सबसे अधिक 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जैसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के बाद अब जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शीघ्र चालू होने वाला है। जेवर एयरपोर्ट के शुभारंभ से उत्तर प्रदेश एयर कार्गो हब के रूप में उभरेगा और निवेश व रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। इसके शुरू होने के बाद यह उत्तर प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा। जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ दिल्ली-एनसीआर की वैश्विक कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देने के लिए तैयार है। यह एयरपोर्ट नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य पर काम करने वाला अत्याधुनिक एयरपोर्ट होगा, जिसमें स्विस दक्षता और भारतीय आतिथ्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। प्रारंभिक चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक आर्थिक हब का काम करेगा। यह एयरपोर्ट न केवल बुनियादी सुविधाओं को नई ऊंचाई देगा, बल्कि पश्चिमी यूपी के युवाओं के लिए रोजगार और संभावनाओं के अनगिनत द्वार खोलेगा।

"UP पॉलिटेक्निक में नकल पर प्रतिबंध, आरोपित विद्यार्थियों की राज्य स्तरीय सुनवाई"

लखनऊ: प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने परीक्षा प्रणाली की साख बनाए रखने के लिए नकल और अनुचित साधन के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए छात्रों को एक अवसर भी दिया है। नवंबर–दिसंबर 2025 की डिप्लोमा परीक्षाओं में नकल के आरोप झेल रहे विद्यार्थियों की राज्य स्तरीय सुनवाई आयोजित की जा रही है, जिसमें उन्हें अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका मिलेगा।

प्राविधिक शिक्षा परिषद के अनुसार, पश्चिमी, मध्य, बुंदेलखंड और पूर्वी क्षेत्र की विभिन्न पालिटेक्निक संस्थाओं से जुड़े सभी आरोपित छात्र-छात्राओं को दस फरवरी को लखनऊ स्थित प्राविधिक शिक्षा परिषद कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह सुनवाई अंतिम अवसर के रूप में दी जा रही है। निर्धारित तिथि और समय पर अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की जिम्मेदारी स्वयं उनकी होगी। यदि कोई छात्र सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके मामले में एकतरफा निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे में भविष्य में किसी प्रकार की आपत्ति या दावा मान्य नहीं होगा। इस निर्णय से परिषद ने यह संकेत दे दिया है कि परीक्षा में अनुशासन और ईमानदारी से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

"पतंग की तार ने लखनऊ मेट्रो की गति प्रभावित की, सिग्नल व्यवस्था में समस्या"

सोमवार को राजधानी लखनऊ में पतंगबाजों की गतिविधियों के कारण लखनऊ मेट्रो का संचालन प्रभावित हुआ। शहर में पतंगों में लगे लोहे के तार की डोर ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन (ओईएच) से टकराने के कारण मेट्रो सेवा प्रभावित हुई। इस घटना के चलते कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन से सिंगारनगर स्टेशन तक मेट्रो का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सका।चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक मेट्रो की रफ्तार अचानक धीमी हो गई। दोपहर लगभग एक बजे तकनीकी गड़बड़ी के कारण मेट्रो कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर करीब दस मिनट तक खड़ी रही। इसके बाद मेट्रो को सिंगारनगर स्टेशन से पहले ब्लॉक क्षेत्र में रोक दिया गया। ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन से लोहे की तार छूने की वजह से ट्रिपिंग हुई, जिससे 15 मिनट तक व्यवधान बना रहा। इस व्यवधान का प्रभाव लखनऊ मेट्रो की बाकी सेवाओं पर भी पड़ा।ट्रांसपोर्टनगर मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को पांच से दस मिनट तक इंतजार करना पड़ा। मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद भी मेट्रो की रफ्तार सामान्य से काफी धीमी रही और हजरतगंज तक यात्रियों को अधिक समय लगना पड़ा। इससे यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई और उनके गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई।मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी टीम ने तुरंत स्थिति का मूल्यांकन किया और प्रभावित क्षेत्रों में मेट्रो सेवा को सामान्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार कोई भी आपातस्थिति या तकनीकी गड़बड़ी होने पर तुरंत सेवाओं को नियंत्रित किया जाता है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि पतंगबाजों द्वारा ओवरहेड लाइन के पास पतंग उड़ाना मेट्रो संचालन के लिए जोखिम भरा हो सकता है। लोहे की तार वाली पतंगें सीधे ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन से टकरा सकती हैं और इसके कारण ट्रिपिंग या तकनीकी बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे मामलों में यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ सकता है।यात्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेट्रो सेवा में देरी से उन्हें अपनी दिनचर्या में कठिनाई हुई। कई यात्रियों ने मेट्रो अधिकारियों से यह मांग की कि शहर में पतंगबाजी के समय और स्थान को नियंत्रित किया जाए ताकि भविष्य में मेट्रो संचालन में व्यवधान न आए।मेट्रो अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी समस्या का समाधान कर दिया गया है और मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि मेट्रो यात्रा करते समय धैर्य बनाए रखें और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि पतंगबाजी जैसे सामान्य दिखने वाले कार्य भी शहरी परिवहन पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। मेट्रो प्रशासन लगातार तकनीकी निगरानी और सुरक्षा उपायों के जरिए ऐसे व्यवधानों को कम करने की कोशिश कर रहा है।मेट्रो अधिकारियों ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पतंगबाजी के समय और स्थान पर नियंत्रण किया जाएगा। इस प्रकार, लखनऊ मेट्रो की सेवाओं में सोमवार को पतंगबाजों की वजह से उत्पन्न हुई देरी ने यात्रियों को असुविधा दी।

"लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने डिप्टी CM के आवास घेरा"

एक बार फिर 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से अभ्यर्थी नाराज है। इसी को लेकर केशव प्रसाद के घर के सामने धरने पर बैठे थे। अभ्यर्थियों ने यहां जोरदार नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। यहां बैठे अभ्यर्थी केशव चाचा न्याय करो का नारा लगाकर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सभी को बस से धरना स्थल इको गार्डेन भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया था सरकार उसे जानबूझ कर लटका दिया जिससे यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सरकार के पास पर्याप्त समय था वह हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का पालन करके सबके साथ न्याय कर सकती थी। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद बीते 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया। लेकिन सरकार इस प्रकरण में हीला हवाली करती रही।

"मोहल्ले में दस दिन से सड़कों और घरों में जमा गंदा पानी"

लखनऊ। बुलाकी अड्डा के पास स्थित सादिक भदेवां मोहल्ले के करीब 250 परिवार दस दिन से गंदे पानी की सड़ाध से परेशान हैं। परिवार के लोग सड़क, गली में भरे गंदे पानी के बीच से आवागमन करने को बेबस हैं। उनकी समस्या को न ही क्षेत्रीय विधायक सुन रहे और न ही पार्षद। जबकि पीड़ित परिवारों के घरों के पास ही पार्षद का भी निवास है। जल निकासी की व्यवस्था पहले से थी, मगर उसका रास्ता संकरा होने के कारण घरों से जितना गंदा पानी नालियों में आता, वह निकल नहीं पाता है। निमेंद्र सिंह व नितिन सिंह के मुताबिक बिना बारिश के ही एक-एक फीट तक सड़क व गली में पानी भरा है। इससे घरों में जबरदस्त सीलन हो रही। साथ ही, परिवार की महिलाओं, बच्चों व पुरुषों को इसी गंदे पानी के बीच से ही गुजरना पड़ रहा है। मोनू गुप्ता ने बताया कि बारिश में नाली का पानी घरों में घुस जाता जो 20-20 दिन तक भरा रहता है। मोहल्ले के लोग विधायक व पार्षद से नाले को सही कराते हुए उसे चौड़ा कराने की फरियाद कर चुके, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 10 दिन से भरे गंदे पानी के कारण बीमारी फैलने लगी है।

"लखनऊ में म्युनिसिपल बॉन्ड लाभकारी, 70 करोड़ का लाभ, बढ़ी सीमा से शहर के विकास को मिलेगा बढ़ावा"

म्युनिसिपल बा ॅन्ड लाभकारी योजना साबित होने के कारण ही छह माह पहले प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में हुई बैठक में लखनऊ समेत अन्य नगर निगमों को अन्य योजनाएं तैयार करके म्युनिसिपल बा ॅन्ड लाने को कहा गया था। इसका मकसद था कि निकायों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। देश के कई निकायों से यह रिपोर्ट भी ली गई थी कि वहां पर किस तरह से म्युनिसिपल बान्ड का उपयोग हो रहा है। इसमें डिग्री कालेज, अस्पताल और लंदन आइ की तरह कोई पार्क बनाए जाने की जानकारी दी गई थी। अब केंद्रीय बजट में म्युनिसिपल बा ॅन्ड की लिमिट दो सौ करोड़ से बढ़ाकर एक हजार करोड़ किए जाने और सौ करोड़ की छूट के प्रावधान की घोषणा से नगर निगम उन योजनाओं को ला सकता है, जो उसके लिए लाभकारी हो सकता है। किसी योजना के लिए बजट का रोना नहीं

पड़ेगा। लखनऊ के बाद गाजियाबाद ने 150 करोड़, आगरा ने 50 करोड़, प्रयागराज ने 50 करोड़ और वाराणसी ने 50 करोड़ के म्युनिसिपल बान्ड जारी किए थे। दो दिसंबर 2020 को मुंबई स्थित राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज में बेल सेरेमनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हुए थे। यह बान्ड बाम्बे स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के साथ ही कारोबार के लिए उपलब्ध हो गया था।

"हाथरस CMO कार्यालय में महिला बाबू 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई"

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय में तैनात एक महिला बाबू को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई सोमवार को दिन में लगभग 12 बजे की गई। गिरफ्तार की गई महिला बाबू का नाम बबीता चौहान बताया गया है, जो सीएमओ कार्यालय में आईटीआई मेडिकल बोर्ड कक्ष में तैनात थी।जानकारी के अनुसार, महिला बाबू पर आरोप है कि उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में इंटर्नशिप अलॉटमेंट के नाम पर एक अभ्यर्थी से 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की थी। शिकायत की जांच और सत्यापन के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर महिला बाबू को रिश्वत लेते हुए पकड़ने की योजना बनाई।शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने पहले पूरे मामले की गोपनीय जांच की। जांच के दौरान यह पाया गया कि शिकायतकर्ता से इंटर्नशिप अलॉटमेंट की प्रक्रिया के लिए अवैध रूप से पैसे मांगे गए थे। शिकायत सही पाए जाने पर एंटी करप्शन टीम ने नियमानुसार ट्रैप कार्रवाई की अनुमति ली और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद टीम ने शिकायतकर्ता को आवश्यक निर्देश दिए और उसे चिन्हित नोट उपलब्ध कराए गए।सोमवार को तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता सीएमओ कार्यालय पहुंचा। उस समय महिला बाबू बबीता चौहान अपने निर्धारित कक्ष में बैठी हुई थी। जैसे ही शिकायतकर्ता ने महिला बाबू को रिश्वत की रकम सौंपी, पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला बाबू को रंगे हाथ पकड़ लिया। रिश्वत की राशि 5,000 रुपये महिला बाबू के पास से बरामद की गई, जिनके नंबर पहले से रिकॉर्ड में दर्ज थे।रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद महिला बाबू ने मौके पर शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर सीएमओ कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारी और अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे कार्यालय में अफरा-तफरी और खलबली मच गई। कई कर्मचारी इस कार्रवाई को देखकर हैरान रह गए।एंटी करप्शन टीम ने मौके पर सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं। महिला बाबू को तुरंत अपने साथ सरकारी वाहन में बैठाया गया। सुरक्षा और प्रक्रिया के तहत पहले महिला बाबू को महिला थाने ले जाया गया, जहां प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद एंटी करप्शन टीम महिला बाबू को कोतवाली हाथरस गेट लेकर पहुंची।कोतवाली में महिला बाबू से विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान रिश्वत मांगने और लेने से संबंधित तथ्यों की जांच की गई। एंटी करप्शन टीम ने महिला बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। टीम ने बताया कि मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी और यदि इसमें किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई

की जाएगी।एंटी करप्शन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। सरकारी कार्यालयों में किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि यदि किसी सरकारी कार्यालय में उनसे किसी भी काम के बदले रिश्वत मांगी जाती है तो वे बिना डरे एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराएं।इस घटना के बाद सीएमओ कार्यालय में सुरक्षा और प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यों को पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार करें। साथ ही कार्यालय में कामकाज की प्रक्रिया की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई की काफी चर्चा रही। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि रिश्वत मांगने की यह घटना किसी व्यक्तिगत स्तर पर थी या इसके पीछे कोई संगठित व्यवस्था काम कर रही थी।इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना कितना आवश्यक है। एंटी करप्शन विभाग का कहना है कि भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ताकि सरकारी सेवाओं में ईमानदारी और विश्वास को मजबूत किया जा सके।

दो दिन बाद खुला उन्नाव अस्पताल, जुकाम-बुखार के मरीजों की लगी लंबी कतार

उन्नाव जिला अस्पताल में दो दिन के अवकाश के बाद सोमवार को ओपीडी खुलते ही मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके तीमारदारों की आवाजाही बढ़ गई, जिससे पंजीकरण काउंटरों पर लंबी कतारें लग गईं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, एक ही दिन में एक हजार से अधिक मरीजों ने ओपीडी में पंजीकरण कराया। चिकित्सकों के मुताबिक, इस समय जुकाम, बुखार, खांसी और वायरल संक्रमण से पीड़ित मरीज सबसे अधिक संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौसम में अचानक आए बदलाव को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। दिन में तेज धूप और रात में बढ़ती ठंड लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रही है। खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग वायरल संक्रमण की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में तैनात चिकित्सक डॉ. कौशलेंद्र ने बताया कि इन दिनों वायरल फीवर के साथ सर्दी-खांसी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मौसम में उतार-चढ़ाव के चलते लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। डॉ. कौशलेंद्र ने मरीजों को रात के समय ठंड से बचाव करने, गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। वहीं, चिकित्सक डॉ. ब्रजकिशोर ने बताया कि ओपीडी खुलते ही मरीजों का दबाव काफी अधिक रहा। अधिकतर मरीज सामान्य वायरल संक्रमण से पीड़ित थे, जिनका इलाज दवाओं और उचित परामर्श से किया जा रहा है। कुछ मरीजों को तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी और कमजोरी की शिकायत थी, ऐसे मरीजों को विशेष निगरानी में रखा गया। मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त व्यवस्था की। पंजीकरण काउंटरों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई और डॉक्टरों ने भी समय से पहले ओपीडी शुरू कर दी, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को देखा जा सके। इसके बावजूद, भीड़ अधिक होने के कारण कई मरीजों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।

बनारस से 40 युवक फरार, 2500 मोबाइल नंबर पर एसआईटी की नजर; जांच में बड़े खुलासे

कफ सिरप मामले में एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और जांच के दौरान नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इस मामले में एसआईटी ने कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की सूची तैयार की है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद और बिक्री में शैली ट्रेडर्स का नाम शामिल है। एसआईटी ने इस संबंध में उन लोगों की पहचान की है जो शैली ट्रेडर्स के माध्यम से कफ सिरप की लेनदेन में जुड़े हुए थे।कमिश्नरेट की एसआईटी ने लगभग 2500 मोबाइल नंबरों को रडार पर रखा है। इन नंबरों का उपयोग कफ सिरप की खरीद और बिक्री में किया गया था। इसके साथ ही पक्के महाल, मैदागिन और सप्तसागर दवा मंडी जैसे क्षेत्रों में रहने वाले कम से कम 40 युवकों ने अचानक बनारस छोड़ दिया है। एसआईटी इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि ये युवक कहाँ गए हैं और उनकी वर्तमान लोकेशन क्या है।जांच में यह भी सामने आया है कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के कुछ पूर्व छात्र नेता भी इस मामले में शामिल हैं। शैली ट्रेडर्स के प्रोपराइटर भोला प्रसाद जायसवाल और उनके पुत्र शुभम जायसवाल के संपर्क में रहने वाले लोगों की सूची एसआईटी ने तैयार की है। इस सूची में उनके परिवार और परिचित शामिल हैं, जिनका कफ सिरप की खरीद और बिक्री में सीधा संबंध था।एसआईटी की जांच में औसानगंज क्षेत्र में रहने वाले पिता-पुत्र और उनके अन्य रिश्तेदारों की संलिप्तता भी उजागर हुई है। जांच के अनुसार, पक्के महाल क्षेत्र के नव युवक सबसे अधिक सक्रिय पाए गए। तीन साल की अवधि में इन युवकों ने होटल, गेस्ट हाउस और प्रॉपर्टी डीलर के व्यवसायों में निवेश किया है। एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है कि इन निवेशों की राशि कहां से आई और उनकी संपत्ति के स्रोत क्या हैं।कोतवाली क्षेत्र के कुछ युवकों से पूछताछ की जा चुकी है। जांच में यह सामने आया है कि सिगरा थाना क्षेत्र के बादशाहबाग कॉलोनी निवासी शुभम जायसवाल, खोजवा के दिवेश जायसवाल और सोनिया के अमित जायसवाल के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, शुभम जायसवाल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जारी किया गया है।जांच अधिकारियों के अनुसार, कफ सिरप मामले में कई आरोपियों की संपत्तियां जब्त की गई हैं। एसआईटी शुभम और भोला जायसवाल के करीबी लोगों की संपत्तियों का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। जांच का उद्देश्य यह है कि यह पता लगाया जा सके कि तीन साल के दौरान कितनी संपत्तियां बनाई गई हैं, ये संपत्तियां कैसे और किस स्रोत से बनी हैं, और उनके आय के स्रोत क्या हैं।एसआईटी की टीम ने प्रारंभिक तौर पर यह पता लगाया है कि कफ सिरप की तस्करी और इसके लेनदेन में शामिल लोग विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे। इस मामले में स्टॉक और वितरण के पैटर्न की भी जांच की जा रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल कफ सिरप की तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वित्तीय लेनदेन, संपत्ति निर्माण और अवैध व्यापार का भी व्यापक जाल है।एसआईटी की जांच के अनुसार, शुभम जायसवाल और उनके संपर्क में रहने वाले लोग कफ सिरप की खरीद और बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इनके माध्यम से स्थानीय और बाहरी स्तर पर कफ सिरप का वितरण किया जा रहा था। जांच अधिकारियों का कहना है कि मामले में शामिल युवकों ने तस्करी के पैसों का उपयोग विभिन्न प्रकार के निवेश में किया।जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में कई परिवार और उनके रिश्तेदार शामिल थे। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिली कि परिवार के सदस्य भी खरीद और बिक्री की गतिविधियों में संलिप्त थे। एसआईटी इस बात की पुष्टि कर रही है कि इन गतिविधियों में किस-किस का योगदान था और किस स्तर तक ये लोग शामिल थे।

"2283 करोड़ बढ़ा DRDO का बजट, कानपुर के रक्षा प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार"

वित्त मंत्री ने रक्षा संगठन डीआरडीओ के बजट में 2283 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करने का एलान किया है। बजट बढ़ने से रक्षा उत्पादों के निर्माण, तकनीक और शोध में विकास होगा। इसका सीधा असर कानपुर स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला रक्षा सामग्री एवं डीएमएसआरडीई को भी मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा संगठन डीआरडीओ के सालाना बजट में 2283 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करने का एलान किया है। सालाना बजट बढ़ने से रक्षा उत्पादों के निर्माण, तकनीक और शोध में विकास होगा। इसका सीधा असर कानपुर स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (डीएमएसआरडीई) को भी मिलेगा। डीएमएसआरडीई तीनों सेनाओं के लिए जरूरी रक्षा उत्पादों के प्रोटोटाइप तैयार करने के साथ-साथ तकनीक और जरूरी सुविधाओं को विकसित करने के लिए नई खोज और शोध करता है। बजट बढ़ने से रक्षा अनुसंधान में तेजी आएगी। डीएमएसआरडीई ने देश के सबसे सशक्त ब्रह्मोस मिसाइल के स्वेदशी रैमजेट ईंधन को विकसित किया है। अभी तक यह नेफथाइल ईंधन अमेरिका समेत दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। डीएमएसआरडीई की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा लेवल-छह श्रेणी की देश की सबसे हल्की बुलेटफ्रूफ जैकेट भी बनाई है। बैलेस्टिक हेलमेट, ब्लास्ट प्रोटेक्शन सूट और एंटी माइन बूट, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल खतरों से सुरक्षा देने के लिए एनबीसी सूट सशस्त्र बलों के लिए बनाया है। नेवी के लिए समुद्री खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाली पॉलीमर मेंब्रेन भी विकसित की है। कानपुर स्थित एचएएल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को विमान, रक्षा एयरक्राफ्ट और कलपुर्जों को विदेशों से मंगवाने पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में छूट का प्रावधान किया गया है। इसका सीधा असर स्वेदश में तैयार होने वाले विमानों, उनकी मरम्मत और रक्षा उपकरणों की ओवरहॉलिंग में लागत और खर्च पर पड़ेगा। एचएएल कानपुर में विमानों की मरम्मत होती है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में तोपों समेत रक्षा हथियारों और उत्पादों की ओवरहॉलिंग होती है, जिसमें आने वाला खर्च कम होगा। एयरक्राफ्ट, विमान, रक्षा उपकरणों के कलपुर्जों को मंगवाने पर कस्टम ड्यूटी में कमी का फायदा रक्षा प्रतिष्ठानों को मिलेगा। मेंटेनेंस,ओवरहॉलिंग के काम में लागत कम होने का फायदा निर्माणियों को मिलेगा।

कानपुर में जोरदार धमाका, 4 बच्चों की हालत गंभीर

कानपुर में धमाके से चार बच्चे झुलस गए। 2 बच्चे के चेहरे की पूरी खाल जल गई। घायलों को जिला अस्पताल उर्सला में एडमिट करा गया गया है। बच्चे खेत से घर आ रहे थे। रास्ते में एक पॉलीथीन में उन्हें राख जैसा कुछ मिला, उसे लेकर वह घर आ गए। घर के बाहर बच्चों ने जैसे ही आग जलाकर पॉलीथीन में उसमें डाली, विस्फोट हो गया। चारों बच्चे गंभीर झुलस गए। पुलिस और फोरेंसिक विस्फोट किससे हुआ इसकी जांच में जुटी है। घटना संचेड़ी थाना क्षेत्र का है। डीसीपी वेस्ट एसएम आसिम काबिदी ने बताया कि रविवार दोपहर 1 बजे सचेंडी पुलिस को सूचना मिली कि विस्फोट से चार बच्चे झुलस गए हैं। इन बच्चों का नाम निहाल, करिया, ऋषि और कृष्णा है। इसमें निहाल और करिया सगे भाई हैं। इन सभी की उम्र 7 से 8 साल है। ये सभी बच्चे दोपहर 12 बजे शौंच करने के लिए एक साथ घर से निकले थे। वहां से लौटने के दौरान बच्चों को रास्ते में राख की तरह पॉलीथीन में कोई विस्फोटक मिला। बच्चे उसे उठा लाए। घर के बाहर बच्चों ने आग जलाई और उसमें पॉलीथीन रखी। वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। चारों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। परिवार के लोग पास के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इन सभी का प्राथमिक उपचार कराने के लिए जिला अस्पताल उर्सला में एडमिट करा गया गया है। बच्चों को इलाज चल रहा है। निहाल के पिता दीनू वही ने बताया कि बच्चे कही से कूड़ा बिनकर लाये थे उस कूड़े में एक पन्नी में कुछ विस्फोटक पदार्थ था। बच्चों ने आग जलाई और पालीथीन उसमें डाल दी। इसके बाद उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट में चार बच्चे झुलस गए। जिस जगह घटना हुई।

CM योगी: कर्तव्य भवन से पेश हुआ यह पहला बजट, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन के प्रति और कर्तव्य भवन में बने पहले बजट की प्रस्तुति के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि बजट में नए व विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि स्पष्ट दिख रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट पर सोमवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने आम बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन वाला बताया। इस अवसर पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट प्रदेश के आम जन के जीवन को सरल बनाने में मददगार होगा। बजट में युवा, गरीब व वंचित के समान विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें हर नागरिक के मूल कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इसमें किसान, युवा, महिला व गरीब का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश राज्य का बजट भी इसी तर्ज पर लाएंगे जिससे विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और यूपी के युवाओं के लिए बड़ा स्थान मिलेगा। बजट में बड़ा हिस्सा यानी 10 हजार करोड़ रुपये एमएसएमई के लिए रखा गया है। इससे हमारे कारीगरों के उत्पाद को बढ़िया लाभ मिलेगा। विश्वकर्मा सम्मान प्रोत्साहन की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ मिल रहा है। राज्य ने ओडीओपी के उत्पादों का एक्सपोर्ट शुरू किया है, इसको इस बजट से बड़ा लाभ मिलेगा। पैकेजिंग के लिए यूपी आगे बढ़ेगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। बजट से रेलवे के सात कॉरीडोर को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक का बड़ा हब तैयार होगा। बजट में मल्टीलेवल लॉजिस्टिक हब के लिए बड़ा लाभ है। अयोध्या जी से हल्दिया के बीच में वाटर वे का उपयोग करने में बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश 10 हजार करोड़ के बायोफार्मा का ग्लोबल हब बनेगा। हम इसी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फार्मा का आयोजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर डाटा सेंटर भी बन रहा है। यूपी में महिला कार्यबल अलग-अलग सेक्टर में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। महिलाओं के सुरक्षित हास्टल को बढ़ाया जाएगा और बजट से छात्राओं के लिए शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को टूरिज्म हब के रूप में बढ़ाया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने इस बजट में 15 आर्कलॉजिकल साइट्स के अलग धन की व्यवस्था की है। अलग बजट मिलने से इसको गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा या यूपी अथारिटी क्षेत्र में सेमी कण्डकटर को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सम्भावना है। इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट के लिए पहले से दो लाख करोड़ में अब और बढ़ावा मिलेगा। अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में यह बजट काफी सहयोगी सिद्ध होगा। प्रदेश में 98 जिला स्तरीय अस्पताल हैं, इनके इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विकास खर्च, सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर और सात रेल कारिडोरों के लिए बजट में प्रविधान किया गया है। आयुष सेक्टर को विकसित करने और हेल्थ सेक्टर की मजबूती के लिए प्रयास किए गए हैं।

टैक्स राहत से चमकेगा IT-BPO सेक्टर: यूपी की 12 हजार यूनिट्स को कितना लाभ?

यूपी के 12 हजार आईटी–बीपीओ यूनिट्स को टैक्स से राहत मिलेगी। विदेशी सेवाओं पर 18% जीएसटी खत्म कर दी गई है। इससे सेवा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, बुलंदशहर और झांसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। केंद्रीय बजट में किए गए अहम संशोधन से उत्तर प्रदेश के आईटी, बीपीओ और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ) सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी कानून की धारा 13(8) से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। इससे विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर लग रहा 18 प्रतिशत जीएसटी समाप्त हो जाएगा। इससे यूपी में सक्रिय हजारों आईटी और सेवा निर्यातक कंपनियों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश में वर्तमान में 12 हजार से अधिक आईटी, बीपीओ और केपीओ कंपनियां कार्यरत हैं, जो विदेशी क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैक ऑफिस सपोर्ट, डेटा प्रोसेसिंग, कॉल सेंटर और रिसर्च सेवाएं प्रदान कर रही हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, बुलंदशहर और झांसी आईटी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं।

ढाबे पर मामूली विवाद बना जानलेवा संघर्ष, दो युवकों की मौत

गाजियाबाद में शुक्रवार देर रात एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक सड़क किनारे स्थित ढाबे पर हुए हिंसक संघर्ष में दो युवकों की जान चली गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। यह घटना ट्रांस-हिंडन जोन के अंबेडकर गेट के पास स्थित वैष्णो ढाबे की है। पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार देर रात उस समय की है जब दोनों गुट नशे की हालत में थे और खाना परोसने में देरी को लेकर उनके बीच तीखी बहस हो गई। उसने बताया कि देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया। होटल में मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को घायल अवस्था में पाया। पुलिस ने बताया कि तीनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। ट्रांस हिंडन के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) निमिष पाटिल ने बताया कि मृतकों की पहचान श्रीपाल (25) और सत्यम (26) के रूप में हुई है। दोनों बहराइच जिले के निवासी थे और खोड़ा के नेहरू विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति बयान नहीं दे सका है। पाटिल ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने दो हमलावरों की पहचान सूरज और राजन के रूप में की है, जबकि इस मामले में कई अन्य भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ के लिए चार संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया

SC-ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन का एलान, शंकराचार्य का आशीर्वाद लेकर मैदान में उतरे अलंकार अग्निहोत्री

6 फरवरी तक SC/ST एक्ट वापस लें, नहीं तो केंद्र सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि SC-ST एक्ट के खिलाफ सात फरवरी से दिल्ली में आंदोलन होगा। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने रविवार की शाम केदारघाट स्थित विद्या मठ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। शंकराचार्य का आशीर्वाद लेकर वह मीडिया से रूबरू हुए। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यह मुलाकात राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है बल्कि एक शुभ संयोग है। शंकराचार्य से मुलाकात कर सामाजिक परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इससे पूर्व प्रयागराज में शंकराचार्य ने आमंत्रित किया था लेकिन समयाभाव के चलते पहुंच नहीं सके। शंकराचार्य के काशी आगमन पर मुलाकात का अवसर मिला। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि काशी से व्यक्तिगत जुड़ाव है क्योंकि आईआईटी बीएचयू से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए यहां आना भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों, विशेष रूप से एससी-एसटी एक्ट और प्रस्तावित यूजीसी रेगुलेशन को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। कहा कि 1989 में लागू एससी-एसटी एक्ट देश का सबसे बड़ा काला कानून है। इस कानून के तहत दर्ज लगभग 95 प्रतिशत मामले फर्जी होते हैं, जिनके कारण समाज के बड़े वर्ग को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।